साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 13-19 मार्च, 2023, 2023, वर्ष-8, अंक-48

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

सीएम शिवराज बोले- चिंता न करें, सरकार किसानों के साथ, सर्वे के दिए निर्देश

किसानों की उम्मीदों पर ओलावृष्टि

- शिवराज ने कलेक्टर से चर्चा करते हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली
- कृषि मंत्री ने कहा- किसानों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी
- मंत्री डंग बोले-प्राकृतिक प्रकोप से किसान डरें और घबराएं नहीं
- ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का संयुक्त दल बनाकर कराएंगे सर्वे
- राजस्व विभाग ने फसलों का सर्वे करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए
- फसलों की स्थिति देखेंगे और आकलन के आधार पर पंचनामा तैयार करेंगे
- किसान और रकबा की सूची ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर लगाई जाएगी
- दावे पर संबंधित किसान के खेत का एक बार फिर सर्वे किया जा सकेगा
- राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत क्षतिपूर्ति राशि किसान के खातों में जमा होगी

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश मे मौसम ने करवट ली है। जिलों में बारिश और हवा के कारण मौसम में ठंडक आ गई है। कई जिलों में ओले भी गिरे हैं। भोपाल के साथ ही उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, राजगढ़, विदिशा, छिंदवाड़ा, रीवा और सतना के साथ ही अन्य जिलों में भी ओलों के साथ बारिश हुई है। मंदसौर जिले में कुछ स्थानों पर तो खेतों और हाइवे पर ओलों की चादर बिछी नजर आई। इससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों को पहले ही वर्षा से फसलों में भारी नुकसान हुआ है। अब मावठे ने उन्हें और चिंतित कर दिया है। वर्तमान में प्रदेशभर में गेहूं, रायड़ा, धनिया, अलसी, मैथी आदि फसलें कटाई के बाद खेतों में पड़ी हैं। गेहूं की फसल आड़ी हो गई। इससे पैदावार प्रभावित होगी। किसानों ने शासन से सर्वे कर मुआवजे की गुहार लगाई है। वहीं राजस्व विभाग ने फसलों के नुकसान का सर्वे करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए हैं। वे पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व और कृषि विभाग के कर्मचारियों के संयुक्त दल गठित कर सर्वे कराएंगे। 10 दिन में रिपोर्ट शासन को भेजेंगे

सीएम ने कलेक्टरों से ली जानकारी

प्रदेश भर में हुई अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के बाद मंगलवार को सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को सर्वे के निर्देश दिए। सीएम ने अतिवृष्टि और ओला प्रभावित जिलों के कलेक्टर से चर्चा करते हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। सीएम ने कहा कि बारीकी से प्रभावित गांवों की फसलों और अन्य नुकसान का सर्वे करें। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेंगी। फसल को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि नियमों के तहत किसानों को दी जाएगी।

मंत्री ने देखी फसल की बर्बादी

प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने ओलावृष्टि और असामयिक वर्षा से प्रभावित बड़वानी जिले के कल्याणपुरा सहित विभिन्न ग्रामों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यहां गेहूं, मक्का और अन्य फसलों को काफी नुकसान हुआ है।

मंदसौर में भारी नुकसान

मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर जिले में मंगलवार की सुबह प्राकृतिक प्रकोप से हुए फसल नुकसान का खेतों में जाकर औचक निरीक्षण किया। असमय बारिश और ओला-वृष्टि से फसलों को क्षति पहुंची है।

प्रदेश में असमय हुई वर्षा के संबंध में सुबह मेरी

प्रभावित सभी क्षेत्रों में विस्तार से बात हुई है। टीम फील्ड में है। सर्वे किया जा रहा है। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं और पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। प्रदेश के कुछ स्थानों में ओला वृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है। शीघ्र ही ओला वृष्टि से हुई फसलों के नुकसान का सर्वे कराया जाएगा।
शिवराज सिंह चौहान, सीएम

मध्यप्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने और ओले गिरने से फसलों को

नुकसान हुआ है। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र और प्रदेश में गांव, गरीबों और किसानों की भाजपा सरकार है। कलेक्टरों को तत्काल सर्वे करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं।
कमल पटेल, कृषि मंत्री

बेमौसम बारिश और ओला वृष्टि से किसानों की

गेहूं और चने की फसल को 80 प्रतिशत नुकसान हुआ है। आलू के किसानों को लागत का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार किसानों को बुलाकर चर्चा करें। किसानों को गेहूं की कीमत प्रति क्विंटल तीन हजार रुपए दी जाए। **जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री**

सात दिन में फसल का करो सर्वे, दस दिन के अंदर बांटों राहत राशि

सीएम ने कहा-सर्वे का कार्य पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से हो

मध्यप्रदेश के उज्जैन में सीएम शिवराज ने शुक्रवार को अधिकारियों को जिले में ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान को लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नुकसान का सर्वे सात दिन में पूरा करें और 10 दिन के भीतर राहत राशि बांटना शुरू की जाए। फसल क्षति सर्वे का कार्य पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से किया जाए। फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने की पूरी कार्रवाई गंभीरता से हो। सीएम ने कहा कि खरीफ फसलों के लिए खाद का अग्रिम भंडारण करें। किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय में असुविधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही भुगतान समय पर सुनिश्चित हो। ग्रीष्मकाल में पेयजल की व्यवस्था बेहतर एवं सुचारू बनी रहे। प्रतिदिन जल प्रदाय हो, जहां पेयजल परिवहन की व्यवस्था करना है, उसकी भी तैयारी अग्रिम रूप से कर लें।

गेहूं के उपार्जन की व्यवस्थाएं अच्छी हों

मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा का फॉलोअप हो। इस दौरान जो कमी मिले, उसे पूरा किया जाए। शेष रहे कार्यों को भी पूरा करें। यात्रा तभी परफेक्ट होगी जब जीरो डिफेक्ट होगा। यात्रा की रिपोर्ट भेजी जाए, जिससे कमियों को पूरा किया जा सके। इस बार गेहूं उत्पादन अच्छा होने की संभावना है। किसानों के हित में समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन की व्यवस्थाएं अच्छी हों। उपार्जन व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार भी करें।

-आठ साल में 25486 दिहाड़ी मजदूरों ने ली अपनी जान

खौफनाक: तमिलनाडु पहले व महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर

मजदूरों की खुदकुशी में मप्र देश में तीसरे नंबर पर

भोपाल। जागत गांव हमार

दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्या के मामले में मप्र देश में तीसरे नंबर पर हैं। मप्र में एक ही साल में 4657 दिहाड़ी मजदूरों ने सुसाइड की, जो कि तमिलनाडु (7673) और महाराष्ट्र (5270) के बाद तीसरा सबसे भयावह आंकड़ा है। एनसीआरबी के 2014 से 2021 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो इन 8 सालों में मप्र में 25486 दिहाड़ी मजदूरों ने अपनी जान ली हैं। इस दौरान देशभर के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 2,35,779 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की है। यानी, हर साल देश में 19,631 मजदूर सुसाइड करने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र में 29516 और तमिलनाडु में 44254 लोगों ने अपनी जान खुद ली। दूसरी ओर केंद्र का दावा है कि देशभर में कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बनाया है। इसके तहत जीवन एवं अपंगता, स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण की योजनाएं हैं।

मजदूरों के हितों पर केवल बातें

35 साल से मप्र में मजदूरों के हित पर काम कर रही संस्था ग्राम सुधार समिति के सार्थक त्यागी के मुताबिक सरकारी और निजी स्तर पर मजदूरों के हितों पर केवल बातें होती हैं। जैसे, मनरेगा में मजदूरी 204 रुपए है और जब काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता देने का नियम है, लेकिन नहीं मिलता। निजी स्तर पर हाल और भी बुरा है।

- मप्र के दिहाड़ी मजदूर महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, दिल्ली आदि राज्यों में काम करने जाते हैं। वहां कुछ होने पर सुसाइड करते हैं। राज्य सरकार की कई योजनाएं मजदूरों के लिए चल रही है। संबल योजना में मौत पर तीन से चार लाख का प्रावधान है। पेंशन भी जल्दी लागू कर देंगे।

-बृजेंद्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री, मप्र

-2500 वर्गफीट में 1100 पौधे रोपे, मुनाफा दो बीघा के गेहूं-चने की फसल जितना

गर्म निमाड में कश्मीर वाली स्ट्रॉबेरी की हो रही खेती

खंडवा। जागत गांव हमार

खेती में रिस्क लेकर नई तकनीक का उपयोग करने वाले युवा किसान अब पारंपरिक फसलों से मुंह मोड़ रहे हैं। अमरूद, नींबू, पपीता, संतरे की खेती के साथ ठंडे प्रदेशों वाली स्ट्रॉबेरी तक पैदा कर रहे हैं, वह भी रिकॉर्ड गर्मी वाले निमाड में। साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। स्मार्ट किसान में हम इस सप्ताह बात रहे हैं, खंडवा के 25 किलोमीटर दूर जलकुआं गांव के युवा किसान शिवपाल सिंह पंवार की। उन्होंने खेत की मेड से लगी महज 2500 स्क्वेयर फीट जमीन में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाएं। लागत सिर्फ 5 हजार की और मुनाफा 20 हजार का। वे बताते हैं कि मुनाफे की यह रकम दो बीघा के गेहूं-चना जितनी है। शिवपाल सिंह ने पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की है। वे क्षेत्र के जैविक और उन्नतशील किसान हैं, इसलिए सरकार का कृषि विभाग भी उन्हें हर समय मदद करता है। कृषि विभाग की आत्मा परियोजना ने ही उन्हें स्ट्रॉबेरी के 1100 पौधे फ्री में उपलब्ध कराएं थे। स्ट्रॉबेरी के पौधे का बाजार मूल्य 10 से 15 रुपए तक है।

लोकल मार्केट नहीं है, इंदौर मंडी भेजते हैं स्ट्रॉबेरी

किसान शिवपाल का कहना है कि स्ट्रॉबेरी की बिक्री के लिए लोकल मार्केट नहीं है। यहां के व्यापारी भी बाहर से माल बुलाते हैं। फसल कम दायरे में है तो ठीक है, वरना स्ट्रॉबेरी को बेचने के लिए इंदौर मंडी ही उपयुक्त है। वहां इसके खरीदार व्यापारी अलग से आते हैं। अच्छा भाव मिल जाता है। पहले कोई खरीदार फिक्स नहीं था, फिर हमने एक लोकल व्यापारी से संपर्क किया तो उसने हमें बताया कि हमें कैसे पैकिंग करके बेचना है। इसके बाद हमने स्ट्रॉबेरी को घर पर ही 200-200 ग्राम की पैकिंग शुरू की और थोक में बेचने लगे। थोक में किसान को 40 रुपए प्रति पैकेट यानी 200 रुपए किलो तक भाव मिल जाता है।

मल्चिंग पद्धति से खेती बेहतर, मिल जाता है केंचुआ खाद

किसान शिवपाल सिंह ने स्ट्रॉबेरी के लिए मल्चिंग पद्धति को बेहतर बताया है। इसके लिए खेत तैयार होने के बाद पौधे लगाने के लिए बेड बनाते हैं और उस बेड को पॉलीथीन से कवर करते है। पॉलीथीन का खर्च प्रति एकड़ तीन से चार हजार रुपए तक होता है। हमें तो महज एक हजार रुपए की पॉलिथीन लगी थी। बाकी, फसल में जितना खाद दिया जाए, उतना कम है। मैंने मिर्च की फसल में जो फॉर्मूला चलाया, वहीं स्ट्रॉबेरी की फसल में उपयोग किया। स्ट्रॉबेरी के पौधों में ड्रिप से ही खाद छोड़ा गया। दूसरा, केंचुआ खाद उपयोगी होता है। गांव में सरकारी प्रयोगशाला है, जहां से केंचुआ खाद आसानी से सस्ते रेट पर मिल जाता है।

इस खेती ने इतिहास, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र बदल दिया

शिवपाल सिंह बताते हैं कि इंटरनेट पर खेती-किसानी से जुड़ी फ्री की सलाह उपलब्ध है। स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की तो खेती के नए आयामों से जुड़ा हूं। मैंने पारंपरिक सोयाबीन, कपास की खेती करना छोड़ दी है। सिर्फ मुनाफे के लिए मिर्ची और राशन इतना जैविक गेहूं लेता हूं। इससे खेती का इतिहास बदल गया है। दूसरी ओर अर्थशास्त्र की बात करें तो स्ट्रॉबेरी एक नकदी फसल है। हर दो दिन के अंतराल में उपज निकलती है, उसे तत्काल मार्केट में बेचना पड़ता है। हमारी उत्पादन क्षमता के हिसाब से हमें दो दिन के अंतराल में 2 हजार रुपए तक आमदनी हो जाती है। इससे खरीफ सीजन की अन्य फसलों में खाद-दवाओं की पूर्ति हो जाती है। यहां तक की घर का राशन भी आ जाता है। समय पर नकद पैसा जेब में रहता है, समय रहते फसलों पर दवा-खाद का छिड़काव हो जाता है। साहूकारों से कर्ज लेने की नौबत नहीं आती है। समाज शास्त्र के बारे में शिवपाल सिंह कहते है कि, नई तकनीक के साथ खेती करों तो उसका आनंद कुछ और ही रहता है। स्ट्रॉबेरी की खेती करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। परिवार और रिश्तेदार भी काफी खुश हैं। गांव के लोग खेत की मेड़ तरफ झांकते तक नहीं थे। अब स्ट्रॉबेरी की खेती देखने के लिए लोग खेत आते हैं। रिश्तेदार भी पूछते हैं, कितना मुनाफा हुआ। मैं 12वीं पास हूं, रिश्तेदारों ने सलाह दी थी कि इंदौर-पीथमपुर चले जाओ, वहां नौकरी करो, लेकिन गांव में रहकर खेती का स्वरूप बदला। आज समाज में अलग पहचान है।

-नौकरी गई तो इंदौर से गांव लौटीं, बेटियों को शुद्ध दूध पिलाने पाली थी 10 गाय

-सभी गाय गिर नस्ल की, दूध से डेयरी प्रोडक्ट बनाने के साथ ही गोमूत्र और गोबर से भी कमा रहीं

डेयरी से 1.5 लाख महीना कमा रहीं पायल 00000

राजगढ़। जागत गांव हमार

आज महिला दिवस पर एक ऐसी महिला की कहानी, जिसने अपनी जॉब जाने और पति की दुकान बंद होने के बाद अकेले ही परिवार को संभाला। वो डेयरी चलाकर महीने के डेढ़ लाख रुपए कमा रही हैं। गांव के लोगों को रोजगार भी दे रही है। ये कहानी है राजगढ़ जिले के किलोदा गांव की रहने वाली पायल पाटीदार की। पायल अपने पति, दो बेटियां ज्हानवी (6) और पहर (3) के साथ इंदौर में रहती थीं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद यहीं जॉब करने लगीं। पति का कपड़ों का बिजनेस था, जो कोरोना काल में बंद हो गया। पायल की भी जॉब चली गई। आर्थिक तंगी आ गई तो परिवार ने अपने गांव लौटना ही सही समझा। पायल को अस्थमा है। दोनों बेटियां भी अक्सर बीमार रहती थीं। डॉक्टर ने उन्हें गाय का दूध पिलाने की सलाह दी। शहरों में तो जर्सी गाय का दूध मिलता है। अब गाय का शुद्ध दूध कहां से लाया जाए, इसी सोच ने पायल को बिजनेस आइडिया दिया। उन्होंने दूध का व्यवसाय करने की ठानी।

10 गाय खरीदी थी, डेढ़ साल में 50 हुईं- पायल ने बताया, हमने पहले कुछ डेयरी फार्म पर विजिट किया। काफी रिसर्च करने के बाद गुजरात की देसी गिर नस्ल कि गाय खरीदने का मन बनाया। हमने 10 गिर नस्ल की गाय मंगवाकर डेयरी की शुरुआत की। आज हमारे पास 50 गाय हैं, जिनके दूध से घी भी बनाते हैं। इन गायों का दूध और घी शाजापुर और इंदौर तक जाता है। बेटियों को गाय का शुद्ध दूध दे पा रहे हैं। अब हमने गोबर के प्रोडक्ट भी बनाना शुरू किए हैं। वर्तमान में हम सवा लाख से डेढ़ लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं। साथ ही 5 महिला और 5 पुरुष को नौकरी भी दे रखी है, जो इस काम में मदद करते हैं।

दो साल पहले नहीं था खेती-किसानी से नाता

पायल बताती हैं, मेरे पिता हरीश पाटीदार पाडलिया माता में रहते हैं। वह किसान हैं। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। बचपन से पढ़ाई और बाद में जॉब के कारण शहरों में ही रही हूं। पिताजी किसान हैं, लेकिन दो साल पहले तक मेरा खेती-किसानी से कोई नाता नहीं था। इंदौर में जॉब लगी। मेरी शादी भी किलोदा गांव निवासी पीयूष वरगरिया से हुई। पति इंदौर में ही कपड़ों का व्यवसाय करते थे। जॉब चले जाने के बाद इस एरिया में इंटरेस्ट आया।

सड़कों पर नहीं मिलेंगी आवारा गाय

पायल ने संदेश देते हुए कहा कि देसी गाय के दूध का एक अलग महत्व है। यह अमृत के समान है, लेकिन यहां 25-30 रुपए लीटर बिकता है। दूसरी बात छत्तीसगढ़ में देसी गायों का गौमूत्र 3 से 5 रुपए लीटर बिकता है। गोबर से अगरबत्ती और अन्य प्रोडक्ट बन रहे हैं। मध्यप्रदेश में 10 करोड़ गाय सड़कों पर हैं, जबकि 18 करोड़ लोग हैं। अगर गौ-मूत्र और गाय के गोबर के प्रोडक्ट खरीदने की मुहिम शुरू हो, तो सड़कों पर आवारा गाय नहीं दिखेंगी।

मैं खुद उठाती हूं गोबर, उपले भी बनाती हूं

पायल ने बताया, मैं नागपुर के देवलापार गई थी ट्रेनिंग के लिए, वहां मैंने देखा कि देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से 50 लाख तक की कमाई कर रहे हैं। यहां लोग दूध के लिए जर्सी गाय को पालते हैं, क्योंकि वो दूध ज्यादा देती है। देसी गाय नहीं पालते हैं, जबकि देसी गाय का दूध अमृत के समान है। लोग इस फील्ड में इसलिए नहीं आते, क्योंकि एक वजह तो है गाय के दूध का रेट सही नहीं मिल पाना, जबकि यह दूध इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के साथ ही कैंसर भी खत्म करता है। दूसरा गोबर उठाना, महिलाएं गोबर उठाना नहीं चाहतीं। मुझे भी बदबू आती थी, लेकिन इससे स्वास्थ्य में फायदा हुआ तो आज मैं वो भी करती हूं। गोबर के उपले बनाती हूं।

सुबह 11 से 5 बजे तक भूसा चलाई तो सीधी एफआईआर

फसल में आग दुर्घटना रोकने बनाएं नियम

नर्मदापुरम। नर्मदापुरम जिले में फसल कटाई के दौरान अग्नि दुर्घटना रोकने के लिए प्रशासन ने नियम निर्देश जारी किए है। खेतों में भूसा मशीन चलाने का समय निर्धारित किए गए है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक भूसा मशीन चलाना प्रतिबंधित रहेगा। बावजूद कोई भूसा मशीन चलाता है तो उसके सीधी एफआईआर होगी। हार्वेस्टर मालिक/चालकों को जिले में किसी भी पुलिस थाने में अपना पंजीयन करना जरूरी होगा। जिले में रबी फसल की कटाई का कार्य प्रारंभ होने वाला है। फसल कटाई के दौरान कृषक भाई मुख्यतः भूषा मशीन एवं हार्वेस्टर का उपयोग बिना सुरक्षात्मक उपायों के बहुतायात में करते हैं। पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम न होने के कारण हार्वेस्टर से उत्पन्न होने वाली चिंगारी से खेतों में खड़ी फसल में आगजनी की घटनाएं होती है, जिससे स्वयं किसान के साथ आसपास के खेतों में आगजनी होने के कारण जनधन, पशुधन को भारी मात्रा में नुकसान होता है। ऐसी घटना को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार सिंह द्वारा जिले में रबी फसल कटाई के दौरान अग्नि दुर्घटना रोकने के लिए आदेश जारी किए है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भूसा मशीन का उपयोग सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। समस्त हार्वेस्टर संचालकों से कहा गया है कि वे वे किसी भी पुलिस थाने में अपना पंजीयन मय नाम, पता, मोबाईल नंबर के साथ कराने के बाद ही खेतों में फसल कटाई कराए। फसलों की कटाई में उपयोग किये जाने वाले कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम एवं स्ट्रारीपर का उपयोग अनिवार्य रूप से करें।

फसल कटाई के दौरान हार्वेस्टर संचालक कम से कम दो अग्निशमन यंत्र चालू अवस्था में रखे। इसके बिना फसल कटाई/भूशा मशीन का उपयोग करना निषेध है। इसके अलावा रात्रि में हार्वेस्टर द्वारा फसल कटाई अथवा भूसा मशीन का उपयोग करने से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव अथवा कोटवारको पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

-जनेकृवि में मोटे अनाज पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ

मोटे अनाज का उपयोग बढ़ने से ही मिलेगा छोटे किसानों को फायदा

जबलपुर। जागत गांव हमार

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में मोटे अनाज के उत्पादन, प्रसंस्करण और अनुसंधान पर मंथन करने के लिए देशभर के कृषि विज्ञानी जुटे। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जुड़े। इस अवसर पर संगोष्ठी में केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि श्री अन्न (मिलेट) आज की जरूरत है। आज घर हो या बाहर हमारे पास भोजन तो उपलब्ध है, लेकिन उसमें जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व की कमी है। पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहे इसके लिए थाली में श्री अन्न होना जरूरी है। भारत की अगुवाई में वर्ष 2023 में पूरी दुनिया मिलेट के रूप में मना रही है। मप्र में कृषि को बढ़ावा देने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका सराहनीय रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार मोटे अनाज को दुनियाभर में बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। पुराने समय में भारतीय थाली में आम जनमानस का भोजन मोटे अनाज सुपर फूड ही थे। मोटे अनाज अत्यधिक पोषक, अम्ल-रहित, ग्लूटेन मुक्त और आहार गुणों से युक्त होते हैं।

गेहूं-चावल में रासायनिकों का बेजा उपयोग

संगोष्ठी में सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि साठ के दशक में ज्वार बाजरा रागी की रोटी हर थाली में नजर आती थी। गेहूं, चावल कम ही खाया जाता था। वर्तमान समय में गेहूं-चावल का भोजन में प्रचुरता से उपयोग के साथ ही बंपर उत्पादन के मोह में अंधाधुंध रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग भी किया गया। मिलेट्स के क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा जनजाति क्षेत्रों में उगाई जाने पुरातन किस्मों में हमारी धरोहर व हमारी पहचान है। इस अवसर पर नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर निरूपम मेहरोत्रा, भारतीय एग्रो इकानोमिक रिसर्च सेंटर के जनरल सेक्रेटरी प्रमोद चौधरी के साथ जनेकृवि के कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे।

हर व्यक्ति को पोषक तत्वों की जरूरत-

अध्यक्षीय उदबोधन में कुलपति डा. पीके मिश्रा ने कहा कि मिलेट्स में मौजूद पौषक तत्वों की वजह से यह आज हर थाली की जरूरत बनता जा रहा है। हमें इसके उत्पादन, प्रसंस्करण, अनुसंधान पर और बेहतर काम करना होगा। संचालन अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. अमित शर्मा एवं आभार प्रदर्शन संचालक विस्तार सेवाएं डॉ. दिनकर शर्मा ने किया। इस मौके पर मिलेट्स के विभिन्न आयामों द्वारा तैयार की गई कृषि साहित्य का विमोचन किया गया। डिण्डोरी जिले की लहरी बाई का शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिलों 11 कृषक को भी सम्मानित किया गया।

व्यंजन एवं उत्पाद की प्रदर्शनी :-

इस मौके पर कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, कंगनी, ज्वार, बाजरा जैसे पोषक अनाज की प्रदर्शनी लगाई गई। आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला एवं डिंडोरी के प्रमुख फसल मिलेट्स के विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इस सम्मेलन में फूड फेस्टिवल एवं प्रदर्शनी, लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहीं। इस दौरान मंडला एवं डिंडोरी जिले के स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित मिलेट्स उत्पाद एवं पारम्परिक व्यंजनों का भी प्रदर्शन एवं विक्रय किया गया।

बंगाल-उप्र में उत्पादन बढ़ने का असर

बीते वर्ष के मुकाबले आधे हुए आलू के दाम

इंदौर। जागत गांव महार

होली के दो दिनों के अवकाश के बाद मंडी खुल गई है। इसी के साथ मंडी में आवक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। आलू-प्याज मंडी में खासी मंदी देखी जा रही है। रुके हुए माल की उम्मीद से ज्यादा उत्पादन के आंकड़ों से भी कीमतें प्रभावित हो रही है।

आलू के दामों में एक वर्ष पहले के मुकाबले लगभग 50 प्रतिशत की नरमी देखी जा रही है। बीते वर्ष इस समय आलू के औसत दाम 1400 से 1600 रुपए क्विंटल थे, जो इस वर्ष 700 से 900 रुपए क्विंटल के बीच आकर ठहर गए हैं। आलू के दामों में गिरावट की वजह सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाले क्षेत्र उप्र और बंगाल में आलू का उत्पादन बढ़ने को बाजार में आई नरमी ती वजह माना जा रहा है। उप्र में आलू का उत्पादन इस वर्ष 240 लाख टन होने की उम्मीद है। दूसरी ओर बंगाल में 130 से 140 लाख टन आलू उत्पादन आंका जा रहा है। बीते वर्ष उत्पादन सिर्फ 85 लाख टन था। इंदौर मंडी की बात करे तो चिप्स सोना क्वालिटी आलू भी 800 से 900 रुपये के बीच बिक रहा है। हालांकि मंडी में अभी बेस्ट क्वालिटी आलू की आवक कमजोर बनी हुई है।

किसानों को आगे दामों में तेजी की उम्मीद

व्यापारियों के अनुसार किसान अभी कम दाम देखकर आलू को कोल्ड स्टोरेज में भेज रहे हैं। ऐसे में अच्छे माल की आवक कम है। इस बीच बाहर के बाजारों से भी मांग कमजोर हो गई है। उप्र, गुजरात का आलू अन्य बाजारों में तेजी से जा रहा है ऐसे में मप्र का माल बाहर जाने से भी अटक गया है। आगे इस बात की आशंका है कि आलू के दामों में और भी गिरावट आ सकती है। फिलहाल किसान आगे दामों में तेजी आने की उम्मीद में माल रोक रहे हैं। लेकिन अब उत्पादन के जो आंकड़े आ रहे हैं उससे यह मुश्किल ही दिख रहा है कि आगे दामों को सहारा मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह से इंदौर की मंडी में उप्र से भी आलू की आवक अच्छी मात्रा में शुरू हो जाएगी। ऐसे में आगे दामों में सुधार आने की उम्मीद नहीं है। उप्र का आलू सस्ता बिका तो स्थानीय बाजार में जगह बना लेगा।

-ऑस्ट्रेलिया के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने बाग का भ्रमण कर कला की प्रक्रिया और बारीकियों को भी समझा

बाग शिल्पी निभा रहे पारंपरिक कला को संरक्षित करने में अहम भूमिका

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत प्रवास पर आए ऑस्ट्रेलिया के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने धार जिले के छोटे से कस्बे बाग का भ्रमण कर बाग प्रिंट कला की प्रक्रिया तथा बारीकियों को समझा। प्रतिनिधि मंडल ने बाग प्रिंट के मास्टर शिल्पकार राष्ट्रीय तथा अंर्तराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्पियों से चर्चा की तथा बाग प्रिंट प्रक्रिया को भी जाना। दल के सदस्यों ने कहा कि छोटे से कस्बे के शिल्पियों ने अपनी पुस्तैनी बाग कला से देश-प्रदेश का नाम रोशन किया है। बाग शिल्पी बिरासत में मिली इस कला को संरक्षित तथा प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि बाग प्रिंट के जनक शिल्प गुरू पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, लाईफ टाईम अचिंवमेंट, राज्य स्तरीय विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित स्व. इस्माईल खत्री ने इस कला की शुरुआत की थी। आज भी उनकी इस अदभुत कला की विरासत को उनके पुत्रगण खत्री परिवार इसे निरंतर सजा-सवांर कर नई ऊंचाइयों दे रहे हैं।

इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को बाग प्रिंट के जनक स्व. इस्माईल खत्री के परिवार के सदस्य शिल्पकार मोहम्मद रफीक खत्री, उमर फारूख खत्री,मोहम्मद काजीम खत्री, मोहम्मद आरिफ खत्री, अब्दुल करीम खत्री, गुलाम मोहम्मद खत्री, कासिम खत्री, अहमद खत्री, मोहम्मद अली खत्री ने भी बाग प्रिंट कला से अवगत कराया।

इस अवसर पर शिल्प गुरु (गोल्ड मेडलिस्ट) राष्ट्रीय हस्तशिल्प,हथकरघा, राज्य स्तरीय तथा अर्तराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित शिल्पकार मोहम्मद युसूफ खत्री ने ऑस्ट्रेलिया के दल के सदस्यों को बाग प्रिंट कला की प्रक्रिया, बारीकियों तथा कला से संबंधित विभिन्न जानकारियों से अवगत कराया। साथ ही उनके पुत्र नेशनल अवार्डी बिलाल खत्री ने भी बाग प्रिंट कला की जानकारी दी तथा ठप्पा छपाई का प्रदर्शन किया।

बाग के ट्राइबल फेस्टिवल में विदेशी मेहमान खूब थिरके तथा आनंद भी लिया

इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को बाग प्रिंट के जनक स्व.इस्माईल खत्री के परिवार के सदस्य शिल्पकार मोहम्मद रफीक खत्री, उमर फारूख खत्री,मोहम्मद काजीम खत्री, मोहम्मद आरिफ खत्री, अब्दुल करीम खत्री, गुलाम मोहम्मद खत्री, कासिम खत्री, अहमद खत्री, मोहम्मद अली खत्री ने भी बाग प्रिंट कला से अवगत कराया। बाग के बिलाल खत्री परिवार ने ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का स्वागत किया। प्रतिनिधि मंडल को बाग प्रिंट कला के उत्पाद भी बहुत पसंद आए तथा बाग प्रिंट कला की प्रक्रिया देखकर अभिभूत हो गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि मंडल ने कहा की खत्री परिवार के सदस्य दुनिया के सबसे अच्छे शिल्पी होने के साथ ही साथ अच्छे सेल्समैन भी हैं। ऑस्ट्रेलिया दल के सदस्य अपने भ्रमण से पूर्व स्टेट अवार्डी काजीम खत्री से लगातार सम्पर्क बनाए हुए थे। बाग के ट्राइबल फेस्टिवल में विदेशी मेहमान खूब थिरके तथा आनंद भी लिया।

तापमान की चुनौती से जूझती गेहूं की फसल

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, लहार (भिंड)

पिछले कुछ सालों से हो रहे जलवायु परिवर्तन को देखते हुए यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहने वाली भारतीय कृषि अधिक से अधिक उत्पादन लेने की चुनौती के साथ ही जलवायु परिवर्तन की चुनौती से भी जूझ रही है। इसका ताजातरीन उदाहरण गत वर्ष मार्च माह में बड़े तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। पिछले वर्ष अचानक मार्च माह में तापमान में वृद्धि होने के कारण गेहूं उत्पादन पर बहुत ही प्रतिकूल असर देखने को मिला था। इसके चलते गेहूं का उत्पादन अनुमान के अनुकूल नहीं मिल पाया था।

जलवायु परिवर्तन की चुनौती से आज पूरी दुनियां मैं कृषि पर प्रभाव देखा जा रहा है। भारत मैं भी खेती के ऊपर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिखाई दे रहा है। संपूर्ण उत्तर भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते हुए तापमान का प्रभाव देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं के ऊपर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। जिसका ताजातरीन उदाहरण पिछले वर्ष मार्च माह में बढ़े हुए तापमान के फलस्वरूप देखा गया था। इस वर्ष भी फरवरी माह से तापमान में हो रहे उतार-चढ़ाव को देखते हुए एक बार पुन: किसानों से लेकर कृषि वैज्ञानिकों और सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा तापमान में हो रही वृद्धि से गेहूं की फसल पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का भी गठन किया जा चुका है। इतना ही नहीं स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक में तापमान में हो रही बढ़ोतरी की समीक्षा की गई है।

गेहूं की फसल एक समशीतोष्ण जलवायु की फसल है, जो पककर पूरी तरह से तैयार होने में 140 से 145 दिन तक का समय लेती है। वैज्ञानिक ऐसी किस्में विकसित करने के प्रयास में लगे हैं जो कम समय में पककर तैयार होने के साथ ही अधिक तापमान सहने की क्षमता रखती हों। यदि आने वाले समय में वैज्ञानिक 120 से 125 दिन में पक कर तैयार होने वाली गेहूं की प्रजातियां विकसित कर पाए तो निश्चित रूप से मार्च में बढ़ने वाले तापमान की चुनौती से बचा जा सकेगा। गेहूं के लिए बुवाई के समय 19 से लेकर 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से मार्च माह में गेहूं की फसल की वृद्धि और विकास के लिए 21 से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। यदि मार्च माह में तापमान में बढ़ोतरी होती है और यह 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है तो गेहूं की फसल के लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इससे अधिक तापमान होने पर गेहूं के उत्पादन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अधिक तापमान होने की दशा में गेहूं के दाने पूरी तरह से भर नहीं पाते हैं तथा वह हल्के रह जाते हैं। इससे गेहूं का उत्पादन प्रभावित होता है। गेहूं की फसल में दाने मार्च के दूसरे सप्ताह से लेकर तीसरे और चौथे सप्ताह में पकना शुरू हो जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा सिफारिश की जाती है कि मार्च माह में तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है तो गेहूं की फसल में एक सिंचाई का सहारा लेकर उत्पादन में गिरावट को रोका जा सकता है।

इस वर्ष मार्च माह के पहले ही सप्ताह से मौसम में आई गिरावट को देखते हुए वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले दो-तीन सप्ताह तक यदि ऐसा ही मौसम बना रहा तो कोई कारण नहीं है कि गेहूं की फसल का उत्पादन प्रभावित हो और जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि अगले दो सप्ताह तक तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके चलते अगेती दशा में बोई

गई गेहूं की फसलों से उत्पादन अच्छा मिलने की पूरी संभावना है। देर से बोई गई गेहूं की प्रजातियों की बात करें तो वह भी 15 अप्रैल तक कटने के लिए पककर तैयार हो जाती हैं। इस कारण यदि यह मौसम अनुकूल रहा तो उनसे भी अच्छा उत्पादन मिलने की संभावना है। होली के दिन मौसम के मिजाज में हुए अचानक बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।

वैश्विक स्तर पर बढ़ती गेहूं की मांग को देखते हुए भारत सरकार गेहूं उत्पादन में कमी का जोखिम नहीं ले सकती है। इसके लिए बढ़ते तापमान से होने वाले प्रभाव की निगरानी पीएमओ से लेकर कृषि मंत्रालय तक कर रहा है। गत वर्ष के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो गेहूं उत्पादन में तापमान का प्रभाव देखने को मिला था। वर्ष 2021-22 में मार्च माह में तापमान में बढ़ोतरी के कारण पूरे देश में 107 मिलियन टन के लगभग ही गेहूं का उत्पादन हुआ था। जो कि सरकार के अनुमान के अनुसार कम था। जबकि वर्ष 2020-21 में पूरे देश में 109 मिलियन टन से अधिक गेहूं रिकार्ड उत्पादन हुआ था। इस वर्ष 2022-23 के कृषि मंत्रालय के अनुमानित आकड़ो के अनुसार पूरे देश में 112 मिलियन टन से अधिक रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यदि यह उत्पादन हुआ तो गत वर्ष की तुलना में पूरे देश में 4.5 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो सकेगा। वैश्विक स्तर पर रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे विश्व में गेहूं की मांग काफी बढ़ी है। भारत में गेहूं का अच्छा उत्पादन होता है तो इसका निर्यात होने से देश के किसानों को इसके बढ़ी हुई कीमतों का लाभ मिल सकेगा।

बदलते जलवायु परिवर्तन में बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए इस प्रकार की समस्याएं आने वाले वर्षों में भी देखने को मिल सकती हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझने के लिए एक व्यापक और स्थाई रणनीति बनाए जाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार तथा कृषि वैज्ञानिक कार्य भी कर रहे हैं। इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए किसानों को भी आगे आना होगा। किसानों को चाहिए कि वह गेहूं की तापमान सहनशील प्रजातियों का चयन कर समय से बुवाई करें। मार्च माह में आवश्यकतानुसार तापमान की बढ़ोतरी की दशा में खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, तो कहा जा सकता है के बढ़ते तापमान की चुनौतियों का काफी हद तक सामना किया जा सकता है। साल दर साल पैदा हो रही जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की जरूरत है। चुनौती इस बात की भी है कि किसानों को ऐसी प्रजातियां विकसित करके दी जाए जो कि कम समय में पककर तैयार होने के साथ ही तापमान की बढ़ोतरी को भी सहने की क्षमता रखती हों। इस साल भी किसान, वैज्ञानिक एवं सरकार बढ़ते तापमान की इस चुनौती को लेकर अच्छे खासे चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं इस चिंता से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन प्रकृति का मिजाज किस करवट बैठेगा यह अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। वैश्विक स्तर पर गेहूं की बढ़ती मांग को देखते हुए यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इस साल भी किसानों को गेहूं की अच्छी कीमत मिलने वाली है। खुले बाजार तथा मंडियों में भी गेहूं का भाव एमएसपी से ज्यादा ही रहेगा। ऐसा अनुमान बाजार के जानकार तथा विशेषज्ञ भी लगा रहे हैं। भारत सरकार भी एमएसपी के तहत इस वर्ष 3.5 करोड़ टन गेहूं की खरीद करेगी। इसके अलावा घरेलू तथा निर्यात मांग के बढ़ने के चलते गेहूं की मांग अच्छी रहने वाली है। जिसका लाभ किसानों को अच्छी पैदावार होने के बाद ही मिल पाएगा। ईश्वर ने चाहा और प्रकृति ने साथ दिया तो किसान इस लक्ष्य को पाने में सफल हो सकेंगे।

भारतीय पर्व-परम्पराओं का सबसे महत्वपूर्ण अंग है गौ-वंश

भारतीय सनातनी, हिन्दू परिवारों में होने वाले छोटे से छोटे आनुष्ठानिक कार्यों से लेकर बड़े से बड़े आयोजनों में गाय के पूजन से लेकर उसके सभी उत्पाद जैसे दूध, दही, घृत, गोबर, गौ-मूत्र (पञ्चगव्य) की उपयोगिता अनिवार्य सुनिश्चित की गई है। हिन्दू घरों में प्रतिदिन चूल्हे पर बनने वाली प्रथम रोटी को गाय की रोटी माना गया है, इसे ही हम गौ-ग्रास कहते हैं। प्रात:काल उठ कर हिन्दू परिवार के सदस्य सर्वप्रथम घर में बनी गौ-शाला गौ-शाला में जाकर गाय को प्रणाम कर उसे हरी घास आहार के रूप में समर्पित कराते हैं। गायों का गोबर उठा कर उसे व्यवस्थित रीति से सुरक्षित करना दिनचर्या का अंग होता है। यह दिनचर्या आज भी भारतीय पारम्परिक परिवारों में देखी जा सकती है। प्रात:काल जागरण से लेकर गौ-दोहन, गौ-चारण और सायंकाल गोचर कर गायों का समूह में घर में वापस आने की बेला को पवित्र गोधूलि बेला माना गया है।

स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि
लेखक मध्यप्रदेश गौ-संरक्षण एवं संवर्द्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष है।

गौ-सेवा को अत्यंत पवित्र कर्त्तव्य हमारे भारतीय धर्म शास्त्रों में व्याख्यायित किया गया है। गाय को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। गाय का यह महत्त्व कोटि-कोटि हिन्दू जन-मानस में सदियों से रचा-बसा है। इसी कारण गाय और सम्पूर्ण गौ-वंश को हम आस्था और श्रद्धा के केंद्र में रखते हैं। गाय को भारत की आर्थिक समृद्धि का आधार माना गया है, गौ-वंश को भारतीय कृषि का आधार, पर्यावरण की संरक्षिका, भौतिक विज्ञान के अनुसंधान का केंद्र, आयुर्वेद का आधार सहित विभिन्न विधाओं को प्रभावित करने वाला भारतीय गौ-वंश की महिमा अपार है। भारतीय पारम्परिक पर्वों की श्रंखला में अनेक पर्व तो सीधे गौ-वंश के लिये ही हैं जैसे वत्स-द्वादशी, गोपाष्टमी तथा दीपावली के दूसरे दिन गोवर्द्धन पूजा का पर्व।

भारतीय पर्वों को मनाने की अपनी एक विशिष्ट शैली है, जिसमें तिथि, नक्षत्र, दिन, योग एवं पर्व केंद्रित रीति-रिवाज एवं पर्व का देवता, देवी एवं उनके पूजन, स्मरण आदि का सामाजिक महत्त्व तथा उनमें छिपा विविध प्रकार का अन्वेषण जनित विज्ञान अवस्थित है। अधिकतर विज्ञान का वह पक्ष जिसे हम बोलचाल की भाषा में मनोविज्ञान कहते हैं; पर्वों को आयोजित करने एवं उनके मनाने में जन-मन का अनुरंजन, विनोद, आनंद, उल्लास, मानसिक उमंग ये सब मनोविज्ञान के विविध आयाम हैं। इसकी पुष्टि भारतीय मान्यताओं में प्रकृति की अष्टधा रूपों में अभिव्यक्त है।

भूमिरापोनलो वायु:खं मनोबुद्धिरेव च।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।। की ही अभिव्यक्ति है।

पर्वों की प्रासंगिकता उनके आरम्भिक काल में जितनी थी, आज भी वे सभी भारतीय प्राचीन पर्व उतने ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है; उनके वर्तमान समय में युगानुकूल, सामयिक और नवाचारित स्वरूप में प्रस्तुत कर उन्हें अत्यधिक प्रासंगिक बनाना समय की अनिवार्यता है।

गौ-वंश कभी भी अनार्थिक और अनुपयोगी नहीं होता- आज किसान या गौ-पालकों द्वारा गोवंश को बेसहारा किया जा रहा है। उन्हें यह कह कर घर से बाहर किया जा रहा है कि गाय दूध नहीं दे रही है और बैल की खेती-किसानी में उपयोगिता नहीं रही। कारण अब कृषि का यांत्रिकीकरण हो गया है जबकि तथ्य इसके विपरीत है। गाय दूध दे रही या नहीं, बैल कृषि कार्य करने योग्य है या नहीं गौ-वंश को अनार्थिक और अनुपयोगी नहीं कह सकते। गौ-वंश से हमें गोबर और गौ-मूत्र जीवन भर मिलता है। दूध तो गाय का सबसे सस्ता उत्पाद है किन्तु गोबर और गौ-मूत्र बहुमूल्य उत्पाद या कीमती पदार्थ हैं। गाय का दूध तो मानव के लिये पौष्टिक आहार है किन्तु उससे भी अधिक गौ-वंश का गोबर और गोमूत्र धरती का पोषण आहार है। मानव शरीर और मानवीय बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिये दूध, दही, मही, घी, मक्खन और धरती को स्वस्थ और उर्वरक बनाये रखने के लिये गोबर, गौ-मूत्र धरती का पारम्परिक आहार है। मनुष्य की भाँति धरती को भी पोषण आहार की आवश्यकता है उसकी पूर्ति गौ-वंश से प्राप्त गोबर और गौ-मूत्र से होती है। इतना ही नहीं गोबर और गौ-मूत्र से अनेक उत्पाद आज वैज्ञानिक पद्धति से तैयार हो रहे हैं।

दीपावली और होलिकोत्सव से यदि हम गौ-वंश को जोड़ कर उसका विश्लेषण युगानुकूल, सामयिक और नवाचार के साथ करें तो गौ-शालाओं में आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भरता और स्वावलम्बन के द्वार खोले जा सकते हैं। भारतवर्ष के सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दीपावली और उसके आस-पास की तिथियाँ आर्थिक समृद्धि की देवी लक्ष्मी के पर्व की तिथियाँ हैं। हम गौ-शालाओं से प्राप्त गोबर के अनेक उत्पादों यथा गोबर के दीपक, गमले, पेंट, गौ-मूत्र से बनाये गये गोनाईल आदि के विक्रय से आर्थिक लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार होलिका दहन भी गोबर से बने कण्डों से तथा गौ-काष्ठ से करने का प्रचलन आरम्भ कर, जंगल से लकड़ी काटने में रोक लगा कर पर्यावरण का संरक्षण करने का अभियान चला सकते हैं। जंगल कटने से बचेंगे और पर्यावरण सुरक्षित होगा। मानव की मृत देह का अंतिम संस्कार भी गौ-शालाओं में गोबर से बनने वाले गौ-काष्ठ और गोबर के कण्डों से कर सकते हैं। इस विधि से भी गौ-शालाओं में आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

वैज्ञानिक भी किसानों को कर रहे जागरुक: मिट्टी की सतह पर पराली फैलाने जैसे उपाय अपना रहे

गर्मी गेहूं के दाने को पकने नहीं देगी और अनाज छोटा रह जाएगा

फरवरी में ही बढ़े तापमान ने बढ़ायी गेहूं उत्पादक किसानों की परेशानी

भोपाल। जागत गांव हमार

पिछले 26 सालों से विकास चौधरी, हरियाणा के करनाल जिले में अपनी 28 हेक्टेयर (70 एकड़) जमीन पर गेहूं की खेती करते आए हैं। लेकिन आज तक उन्होंने फरवरी में इतनी गर्मी पड़ते कभी नहीं देखी। करनाल के तरावड़ी गांव में रहने वाले चौधरी ने बताया कि हालांकि पिछला साल भी अप्रत्याशित रूप से गर्म था। मार्च में ही गर्म हवाएं चलने लगी थीं। लेकिन फिलहाल गर्मी को देखते हुए लग रहा है कि निश्चित रूप से इस बार भी यह गेहूं के दाने को पूरी तरह से पकने नहीं देगी और अनाज का आकार छोटा रह जाएगा। पिछले साल मार्च में तापमान काफी बढ़ गया था। इससे उत्पादन पर खासा असर पड़ा और वो 28 क्विंटल प्रति एकड़ से घटकर 23 क्विंटल प्रति एकड़ हो गया। मैंने पिछले साल 21 हेक्टेयर में गेहूं बोया था। प्रति एकड़ पांच क्विंटल के अंतर से किसान को कम से कम 500,000 लाख रुपए का नुकसान होता है। फिलहाल तो हम ज्यादा सिंचाई करने और नमी की मात्रा बनाए रखने के लिए मिट्टी की सतह पर पराली फैलाने जैसे उपाय अपना रहे हैं। चौधरी के तरावड़ी गांव से लगभग 700 किमी दूर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 60 वर्षीय किसान मोहम्मद रियाज भी कुछ इसी तरह के संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आमतौर पर गेहूं की फसल को सिंचाई के तीन चक्रों की जरूरत होती है। लेकिन इतनी गर्मी है कि मैं अपनी गेहूं की फसल को चौथी बार पानी दे रहा हूं। फसल अप्रैल तक कटने के लिए तैयार हो पाएगी। यानी मुझे फसल में कम से कम दो-तीन बार और पानी देना होगा। इससे डीजल पानी के पंपों से सिंचाई की मेरी लागत दोगुनी हो गई है। यह खर्च लगभग 4,200 रुपए हुआ करता था, लेकिन अब मुझे तकरीबन 9 हजार रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे।

किसानों की शिकायतें निराधार नहीं

मौसम की मार के बारे में किसानों की शिकायतें निराधार नहीं हैं। 23 फरवरी को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने एक प्रेस बयान में अगले पांच दिनों में उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना जताई थी। आईएमडी ने चेताया कि सामान्य से अधिक तापमान गेहूं की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बयान में कहा गया था कि दिन में तापमान उच्च बने रहने से गेहूं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि गेहूं की फसल प्रजनन वृद्धि या फूल आने के करीब पहुंच रही है, जो ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाती है। फूल और परिपक्वता के समय उच्च तापमान से उपज में कमी आती है। अन्य फसलों और बागवानी पर भी कुछ ऐसा ही असर पड़ सकता है। नवंबर तक गेहूं की फसल को थोड़ा पहले बोने की वैज्ञानिकों की सलाह के बारे में पूछे जाने पर किसानों ने बताया कि फसल बोने में देरी मानसून की बारिश के देर से आने के कारण होती है।

एंटी-साइक्लोन इसके लिए जिम्मेदार

दिलचस्प बात यह है कि 20 फरवरी को नई दिल्ली में 33.6 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान 2006 के बाद से फरवरी के महीने में सबसे अधिक था। 2006 में 26 फरवरी को 34.1 डिग्री का उच्च तापमान दर्ज किया गया था। फरवरी में इस तरह के अभूतपूर्व उच्च तापमान दर्ज किए जाने के बारे में पूछने पर प्राइवेट मौसम पूर्वानुमान वेबसाइट स्काईमेट वेदर में मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया कि भारत के उत्तरी मैदानों में गर्म हवाओं के आगमन का बड़ा कारण अरब सागर में एक एंटी-सिलोन का बनना है। उत्तर-पूर्वी अरब सागर के आसपास मंडरा रहा यह एंटी-साइक्लोन पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्रों से भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों की ओर गर्म हवाएं भेज रहा है।

हवाएं भी कोई राहत नहीं दे पा रहीं

हवाओं के चलते हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं भी कोई राहत नहीं दे पा रही हैं, जिसके कारण हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इतनी गर्मी पड़ रही है। प्रतिकूल रूप से बदलती जलवायु के आलोक में बदलते मौसम के मिजाज के बारे में बात करते हुए, पलावत ने कहा कि कृषि क्षेत्र पर इसका खासा असर पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि किसानों और सरकार दोनों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लचीले उपायों के बारे में सोचने की जरूरत है। इस साल भी जिन किसानों ने समय से पहले गेहूं बोया था, वे देर से बोने वालों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। किसानों को अपने कृषि कैलेंडर और खेती के समय को फिर से समायोजित करने की जरूरत है। सरकार को गर्मी प्रतिरोधी फसलों के साथ आना होगा।

करनी होगी गेहूं की अगेती बोवनी

करनाल स्थित भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक अनुज कुमार ने कहा कि तापमान के अचानक से बढ़ने की वजह से गेहूं की फसल पर पड़ने वाले प्रभाव की भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर ये गर्मी लंबे समय तक बनी रही, तो उपज निश्चित रूप से प्रभावित होगी। हालांकि मौजूदा समय में हम जिन गेहूं की किस्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे गर्मी सहने योग्य हैं, मगर सिर्फ एक हद तक।

तापमान 30 डिग्री के आसपास मंडरा रहा

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक धीरज तिवारी ने बताया कि फिलहाल गेहूं की फसल जिस अवस्था में है, उसके लिए 20 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस के अनुकूल तापमान की जरूरत होती है। हालांकि तापमान इन दिनों लगातार 30 डिग्री के आसपास मंडरा रहा है। मामले को बदतर बनाने के लिए हवाएं भी जिम्मेदार है। इतना अधिक तापमान गेहूं के दानों को सुखा देगा जिससे उपज पर खासा असर पड़ेगा। किसानों को जरूरत पड़ने पर अपने खेतों को पानी से नम रखने की जरूरत है और साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि जब गर्म हवा चल रही हो तो वे सिंचाई न करें। किसानों को अपनी गेहूं की फसल को समय से थोड़ा पहले बोने की जरूरत है। नवंबर तक, बुवाई पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि गेहूं को कटाई के लिए पकने में लगभग तीन महीने लगते हैं। इस तरह, किसान फरवरी-मार्च में गर्मी की मार से बच सकते हैं।

मानसून में देरी को जिम्मेदार ठहराया

नवंबर तक गेहूं की फसल को थोड़ा पहले बोने की वैज्ञानिकों की सलाह के बारे में पूछे जाने पर किसानों ने बताया कि फसल बोने में देरी मानसून में बारिश के देर से आने के कारण होती है। उन्नाव के भगेड़ी खेड़ा गांव के 42 साल के किसान रणधीर यादव ने शिकायत की कि नवंबर में गेहूं की बोवनी करना उनके लिए असंभव है क्योंकि दिसंबर तक धान की कटाई नहीं हो पाई थी। किसान ने बताया कि मानसून की बारिश सितंबर तक नहीं आई थी। लगातार सिंचाई कर हमने किसी तरह धान की फसल को जिंदा रखा। हालांकि, जब धान की बात आती है तो बारिश का कोई विकल्प नहीं होता है। अक्टूबर तक खेत पानी में डूबे रहे और दिसंबर तक धान की कटाई नहीं हो सकी। मैं दिसंबर में गेहूं कैसे लगा सकता था। मुझे चिंता है कि मुझे धान और चावल में से किसी एक को चुनना पड़ेगा क्योंकि इस तेजी से बदलते मौसम में दोनों फसलों को बनाए रखना मुश्किल है।

आकलन करने के लिए समिति का गठन

केंद्र सरकार ने गर्म मौसम की स्थिति से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिएएक समिति का गठन किया। समिति के गठन की घोषणा के बाद केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा ने प्रेस को बताया कि समिति सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग करने की सलाह के साथ किसानों की मदद करने के लिए आगे आएगी। समिति के सदस्यों में से एक, करनाल स्थित आईआईडब्ल्यूबीआर के निदेशक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि हम किसानों के लिए एक सलाह के साथ सिफारिशें तैयार कर रहे हैं ताकि गेहूं की फसल पर गर्मी के प्रभाव से निपटने के समाधान ढूंढे जा सकें। अगले सप्ताह की शुरुआत में समाधान लेकर आने की उम्मीद है। पिछले साल इसी तरह के मौसम ने भारत के गेहूं उत्पादन को 2.75 मिलियन टन या कुल उत्पादन का 2.5 प्रतिशत कम कर दिया था।

-धर्मकांटा लगाने के प्रस्ताव पर नहीं हो सका अमल

-मंडी समिति ने कहा हमारी तैयारी पूरी, भैंसाखेड़ी मंडी में गेहूं और चना खरीदने की तैयारी

गेहूं की फसल खराब होने से नीलामी में होगा विलंब

भोपाल। जागत गांव हमार

बैरागढ़ के निकट ग्राम भैंसाखेड़ी स्थित पंडित दीनदयाल कृषि उपज मंडी में गेहूं और चना खरीदने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार बेमौसम वर्षा के कारण फसल देर से आने की संभावना है, इसके बावजूद मंडी समिति ने खरीदी की तैयारी शुरू कर दी है। अनाज व्यापारी संघ ने भी इस बार नीलामी में भाग लेने का निर्णय लिया है। उप मंडी का दर्जा प्राप्त इस मंडी को राजधानी की सबसे सुनसान कृषि मंडी माना जाता है क्योंकि यहां पर आने में किसानों की रुचि नहीं है। अनाज व्यापारी भी लंबे समय से उदासीन बने हुए हैं। सीहोर कृषि मंडी एवं गांधीनगर के आसपास की बड़ी अनाज की दुकानों पर किसानों से सीधे खरीदी करने के कारण बैरागढ़ की मंडी की रौनक कम हो गई है। हालांकि कृषि उपज मंडी समिति लंबे समय से मंडी को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। समिति ने व्यापारियों को कई बार नोटिस देकर यहां कारोबार नहीं करने पर लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी है। समिति के प्रयास से अब साल में दो बार अनाज की खरीदी होने लगी है। इस माह गेहूं एवं चने की फसल आने वाली है। मंडी समिति चाहती है किकिसान और व्यापारी दोनों यहां आकर नीलामी में भाग लें।

धर्मकांटा लगाने का प्रस्ताव भेजा

बैरागढ़ एवं आसपास के किसान एवं अनाज व्यापारी लंबे समय से यहां पर धर्मकांटा लगाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन दो साल बाद भी यह नहीं लग सका है। अब मंडी समिति ने इसी सीजन में धर्मकांटा लगाने का प्रस्ताव शासन भेजा है। माना जा रहा है किधर्मकांटा लगने से किसानों और व्यापारियों को सुविधा हो जाएगी। फिलहाल अनाज इलेक्ट्रानिक कांटों की मदद से तोला जा रहा है। मंडी प्रभारी बीएल त्यागी के अनुसार मंडी में जल्द ही धर्मकांटा लगने की संभावना है। अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष जगदीश आसवानी एवं नरेश पारदासानी का कहना है कि मंडी की चहल पहल बढ़ाने के लिए हम पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। किसानों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकिवह फसल बेचने यहां आ सकें।

-ठेकेदार की लापरवाही के कारण काम अधर में लटका पड़ा

गुजरवाड़ा पंचायत में नल-जल की स्थिति खराब, लोग परेशान

भोपाल। जागत गांव हमार

नर्मदापुरम जिले की जनपद पंचायत माखन नगर की ग्राम पंचायत गुजरवाड़ा में हर-घर नल-जल का सपना साकार होता नजर नहीं दिख रहा है। ठेकेदार की लापरवाही के कारण काम अधर में लटका पड़ा है। स्थानीय नागरिक परेशान हो रहे हैं। सरपंच सरपंच प्रताप सिंह यादव ने बताया कि पंचायत में नल-जल योजना का काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन पाइप लाइन डालने के बाद ठेकेदार ही गायब हो गया। इससे गांव के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद सैकड़ों बार फोन लगा चुका हूं, लेकिन ठेकेदार मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। यही नहीं, जगह-जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं। तक कि स्थानीय विधायक विजयपाल सिंह ने भी विकास यात्रा के दौरान ठेकेदार को फटकार लगाते हुए नल-जल का काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन ठेकेदार ने अभी तक कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि पाइप लाइन के साथ ही टंकी का कार्य पूर्ण हो जाए तो कुछ हद तक समस्या दूर हो सकती है।

तोड़ दिया पंचायत का द्वार- सरपंच प्रताप सिंह यादव ने बताया कि ठेकेदार शुरू से ही लापरवाही बरत रहा है। यहां निर्माण कार्य के दौरान पंचायत का मुख्य द्वार ही तोड़ दिया था। जिसे अभी तक नहीं बनाया है। जबकि कहा था कि जल्द ही बना दूंगा। ठेकेदार की मनमानी का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

जल्द बनकर तैयार हो जाएगी गौशाला

सरपंच प्रताप सिंह यादव ने बताया कि पंचायत में जल्द ही सरकारी गौशाला बनकर तैयार हो जाएगी। निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। टीनशेड भी डल गए हैं। कुछ ही काम बचा है, जिसे जल्द ही निपटा लिया जाएगा। इससे सबसे ज्यादा राहत यहां के किसानों को मिलेगी। अभी आवारा मवेशियों से सब परेशान हैं। फसल पक चुकी है। मवेशी घुसकर उजाड़ रहे हैं।

स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं

सरपंच प्रताप सिंह यादव ने चर्चा के दौरान बताया कि हमारे यहां 10वीं तक स्कूल है, लेकिन यहां बच्चों के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक हैंडपंप था वो भी खराब पड़ा है। हमने पंचायत के माध्यम से स्कूल में पानी की व्यवस्था कराई है। उन्होंने बताया कि पंचायत में आंगनवाड़ियां चार हैं, जिसमें दो जर्जर हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा समस्या बरसात के दिनों में होती है। ये दोनों आंगनवाड़ियां डूब में आ जाती हैं। आस-पास पानी की सही निकासी भी नहीं है।

-स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा

अनदेखी से ग्राम पंचायत गोंदलवाड़ा में आंगनवाड़ी-पंचायत भवन जर्जर

भोपाल। जागत गांव हमार

नर्मदापुरम जिले की जनपद पंचायत माखन नगर की ग्राम पंचायत गोंदलवाड़ा में आंगनवाड़ी केंद्र और पंचायत भवन दोनों जर्जर भवन में संचालित हो रहे हैं। इससे पंचायत के साथ ही स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच प्रतिनिधि केशव गढ़वाल ने बताया कि पंचायत में नल-जल योजना का काम पूरा हो गया है, लेकिन अभी हर घर नल से जल नहीं पहुंच रहा है। जगह-जगह से पाइप लाईन फूट गई है। ठेकेदार कहने के बाद भी सुधार नहीं कर रहा है। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि पाइप-लाईन सुधर जाए तो अप्रैल के पहले ही लोगों को योजना का लाभ मिलने लगेगा। गोंदलवाड़ा पंचायत में एक भी सरकारी गौशाला नहीं है। इसका प्रस्ताव बनाकर सरपंच जनपद पंचायत को जल्द ही देने जा रही हैं ताकि लोगों को आवारा मवेशियों की समस्या से छुटकारा मिल जाए।

सरपंच प्रतिनिधि केशव गढ़वाल ने बताया कि हमारे यहां कई घरों में शौचालय भी काफी पुराने हो चुके हैं। इसी तर आंगनवाड़ी केंद्र और पंचायत भवन भी जर्जर हो चुका है। नए निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव दिया है, लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिल है। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचायत में 8वीं कक्षा तक एक स्कूल है, उसके दो कमरों की छत से बरसात में पानी टपकता है। स्कूल के किचनशेड की भी हालत खराब है। हमारा प्रयास है कि बरसात के पहले दोनों कामों को दुरुस्त करा दिया जाए।

बिजली की समस्या बरकरार

सरपंच प्रतिनिधि केशव गढ़वाल ने बताया कि पंचायत में सालों से बिजली की समस्या बरकारा है। बिजली लाइन का केवलीकरण नहीं होने से लोगों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग कटिया फंसाकर बिजली जला रहे हैं। इससे कुछ लोग बिल देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। पंचायत में एक भी अमृत सरोवर तालाब नहीं है। अगर तालाब हो जाए तो खेती का रकबा बढ़ जाएगा। सिंचाई के लिए किसानों का परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने ने बताया कि 29 पीएम आवास स्वीकृत हुए हैं। जिसमें 24 बनकर तैयार हो गए हैं। शेष का निर्माण कार्य चल रहा है जल्द ही पूरा हो जाएगा।

ग्राम सिंदूर सड़क का निर्माण प्राथमिकता

सरपंच प्रतिनिधि केशव गढ़वाल ने बताया कि पंचायत में अगर ग्राम सिंदूर सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण हो जाए तो 90 फीसदी किसानों की समस्या दूर हो जाए। अभी किसान अपने खेतों तक पहुंचने के लिए दूसरे गांवों से चक्कर लगाकर पहुंचते हैं। सड़क की सबसे ज्यादा समस्या गोंदलवाड़ा, बजरापुर और मालनवड़ा में है। यहां सड़क का निर्माण कराना पंचायत की प्राथमिकता में है।

-24 लाख में सिर्फ दीवारें ही बन पाईं

मदउखेड़ी पंचायत में गौ शाला निर्माण में गड़बड़ी

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के विदिशा जिले की कुरवाई जनपद की मदउखेड़ी पंचायत में गौशाला के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि संजय सिंह का कहना है कि गौशाला निर्माण के लिए 24 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई है।

24 लाख रुपए के कामों का मूल्यांकन भी करा लिया गया है, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ दिवारें ही खड़ी हो पाई हैं। इससे गौशाला के निर्माण में भ्रष्टाचार का अंदेशा है। गौशाला निर्माण के लिए 38 लाख रुपए शासन से स्वीकृत हुए थे। इसमें से पूर्व सरपंच के कार्यकाल में 24 लाख रुपए के काम करा लिए हैं। अब स्थिति यह है कि गौशाला में न तो दरवाजे लगे हैं। न टीन सेट बन पाया है। इस मामले की शिकायत भी की गई है, लेकिन जांच तक नहीं हो पा रही है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है।

सचिव बोले-मुझे ज्यादा जानकारी नहीं

मदउखेड़ी पंचायत के सचिव अजब सिंह दांगी का कहना है कि मैं कुछ महीने पहले ही पंचायत में आया है। जो भी काम हुए हैं, वे मेरे आने से पहले हुए हैं। इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इस संबंध पंचायत विभाग के इंजीनियर ही कुछ बता सकते हैं। वे इस मामले की जांच भी कर रहे हैं। जो काम रह गए हैं, उन्हें पूरा किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

-कम संख्या देख किसानों को 10 मार्च तक का समय दिया

इंदौर में 33 हजार किसानों ने कराया समर्थन के लिए पंजीयन

इंदौर। समर्थन मूल्य पर गेहूं का विक्रय करने के लिए इंदौर जिले में कुल 33 हजार 929 किसानों ने अब तक पंजीयन करवा लिया है। दरअसल बीते वर्ष जिले में कुल 37 हजार किसानों ने पंजीयन करवाया था।

किसानों के गेहूं विक्रय के पंजीयन के लिए इंदौर जिले में 62 केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही एमपी आनलाइन कियोस्क से भी आनलाइन पंजीयन की सुविधा दी गई है। इससे पहले पंजीयन की आखिरी तारीख 28 फरवरी दोपहर थी। बाद में सरकार ने तारीख बढ़ाकर 5 मार्च कर दी थी। इंदौर में कम संख्या देख किसानों को 10 मार्च तक का समय दिया गया।

संख्या से चिंतित सरकार- समर्थन मूल्य पर किसान गेहूं बेचे इसे लेकर सरकार खुद चिंतित नजर आ रही है। गेहूं का समर्थन मूल्य इस सीजन के लिए 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बीते वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए था। एमएसपी में 110 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के बावजूद भी सरकार आशंकित है कि ज्यादा किसानों की भीड़ गेहूं बेचने के लिए जुटेगी। बाजार में गेहूं के ऊंचे दाम इसकी वजह बने हुए हैं। बीते साल भी 37 हजार पंजीयन के मुकाबले काफी कम किसान समर्थन मूल्य पर माल बेचने पहुंचे थे। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं की वैश्विक बाजार में किल्लत शुरू हो गई थी।

मप्र में 80 लाख टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य

भारत से निर्यात खोल दिया गया था। ऐसे में खुले बाजार में गेहूं के दाम 3000 रुपए क्विंटल तक पहुंच गए थे। नतीजा हुआ कि किसानों ने समर्थन मूल्य पर सरकार को गेहूं बेचने में रुचि नहीं ली। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चिंता और बफर स्टाक कायम रखने के लिए किसी भी स्थिति में देशभर में 250 लाख टन गेहूं खरीदना चाहती है। मप्र ने राज्य में 80 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। बाजार में यदि कीमतें ऊंची रही तो सरकार और अधिकारियों को चिंता है कि बीते वर्ष की तरह इस बार कम किसान सरकार को गेहूं बेचने आएंगे।

250 लाख टन गेहूं की खरीदी अनिवार्य

कारोबारियों के अनुसार सरकार फिलहाल गेहूं में आयात और निर्यात दोनों पर प्रतिबंध जारी रखेगी। किसानों के हित में आयात को मंजूरी नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर निर्यात खुलने की संभावना फिलहाल नहीं है। दरअसल सरकार को सबसे पहले खाली पड़े सरकारी गोदामों को भरना और बफर स्टाक से ऊपर जाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भी पर्याप्त गेहूं का भंडार करना जरुरी है। सरकार किसी भी स्थिति में इस वर्ष 250 लाख टन गेहूं की खरीदी करना चाहती है। खरीदी के इसी लक्ष्य की पूर्ति के बाद समीक्षा होगी और उसके बाद ही निर्यात की अनुमति दी जा सकती है।

नगरपालिका नए सिरे से कर रही बंजाराडैम को पर्यटक स्थल बनाने की कवायद

50 करोड़ खर्च के बाद भी विरान है डैम

फलीभूत नहीं हो सका केन्द्रीय मंत्री के बंजारा डैम को पर्यटक स्थल विकसित करने का प्रयास

शिवपुरी/श्योपुर। खेमराज मौर्य

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रयास से बंजाराडैम को चंबल सर्किल में जोड़कर शहर को पर्यटन की जो सौगात दी थी वह अधिक नहीं चल सकी। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने बंजारा डैम को विकसित करने के लिए करीब 50 करोड़ रुपए खर्च कर वहां रेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट एवं मोटर बोट नौकायन की व्यवस्था की थी। यह कवायद कुछ समय तक चली लेकिन बाद में ऐसी बंद हुई कि यहां पर्यटन सुविधा कभी शुरू भी हुई दिखाई नहीं पड़ रही। अब नपाध्यक्ष रेनु-सुजीत गर्ग की परिषद ने उक्त बंजाराडेम को दोबारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू की अपील की है।

नगर पालिका ने बंजारा डैम सहित सीप नदी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत परिषद ने अमृत-2 योजना में सीप को जोड़कर प्रस्ताव सरकार को भेजा है। जिसके तहत पर्यटक स्थल को विकसित करने के साथ-साथ सीप नदी के किनारे सड़क ओर निश्चित दूरी पर पार्क विकसित करने का खाका भी तैयार किया है। अगर यह कवायद धरातल पर उतर सकी तो पर्यटन के साथ-साथ सीप का समाप्त होता जा रहा अस्तित्व बच सकेगा।

सीवर योजना देगी सीप को पुनर्जीवन

नगर पालिका ने अमृत टू योजना के तहत शहर में सीवर ट्रीटमेंट प्लान स्वीकृति के लिए भेजा है। अगर यह प्लान स्वीकृत हुआ तो शहर को गंदगी से मुक्ति दिलाने के साथ सीप का सौंदर्यकरण भी हो सकेगा। ज्ञातव्य हो कि सीप में आधा दर्जन से अधिक नाले गिर रहे हैं। जिसमें घरों का गंदा मल मूत्र युक्त पानी बेहकर जा रहा है। पॉलिथीन युक्त पानी सीप में जाने से सीप नाला बन कर रह गई है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के द पानी फिल्टर होकर जीप में जाएगा जिससे सीप प्रदूषण से बचेगी।

-सहकारिता विभाग की परामर्शदात्री समिति की हुई बैठक

किसानों को सहकारी बैंकों ने जारी किए 39 लाख 57 हजार केसीसी

भोपाल।

प्रदेश के किसानों को सहकारी बैंकों द्वारा नवम्बर-2022 तक 39 लाख 57 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा जारी कुल 65 लाख 83 हजार केसीसी में से सहकारी बैंकों की भागीदारी 7 प्रतिशत है। केसीसी से कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण प्रदान किया जाता है। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई। समिति के सदस्य विधायक संजय सत्येंद्र पाठक उपस्थित थे। सचिव सहकारिता विवेक पोरवाल ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन और शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन सफलता से किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर समितियों द्वारा 46 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन किया गया। समितियों द्वारा प्रदेश में 16 हजार 452 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इनसे 119 लाख परिवारों को समय पर राशन वितरित किया जा रहा है। विभाग द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण के वितरण में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की गई है। वर्ष 2022-23 में 14 हजार 699 करोड़ रुपए के ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को को उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों में बैंकिंग सेवाओं का उन्नयन किया जा रहा है। प्रदेश के 29 जिला सहकारी बैंकों से संबद्ध शाखाओं और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में 4 हजार माइक्रो एटीएम स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे समिति स्तर पर किसानों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही राज्य सहकारी बैंक और खरगोन, इंदौर एवं विदिशा जिला सहकारी बैंक में मोबाइल बैंकिंग की सुविधा संचालित की जा रही है।

नकली-मिलावटी दूध और दुग्ध उत्पादों के विरुद्ध विशेष अभियान

भोपाल। नकली-मिलावटी दूध और उससे बने मावा, पनीर आदि दुग्ध उत्पादों की रोकथाम के लिए 2 मार्च से खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा दूध के शुद्धिकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ. सुदाम खाड़े ने बताया कि अभियान में अब तक दूध और दूध से बने उत्पादों के 5133 नमूने लिए गए हैं। विशेष अभियान में नकली-मिलावटी दूध और उससे बने उत्पादों का निर्माण, संग्रह और विक्रय करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा रही है। इन उत्पादों के निर्माण तथा विक्रय से जुड़े 2 संस्थान के लाइसेंस निरस्त किए गए और 4 संस्थान के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराए गए हैं। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा चलित खाद्य प्रयोगशाला और मैजिक बॉक्स से आमजन द्वारा दैनिक उपयोग में लिए जा रहे दूध एवं दुग्ध उत्पादों की मौके पर जांच भी की जा रही है। साथ ही जिलों में संचालित दूध के कलेक्शन सेंटर, चिलिंग प्लांट, दूध का परिवहन करने वाले वाहन सहित मावा, पनीर, घी के खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठानों की सघन जांच भी जारी है।

अखिलेश्वरानंद ने कलेक्टरों को जारी किए निर्देश

जिलों से बाहर भूसा ले जाने पर लगाया जाए प्रतिबंध

भोपाल।

अध्यक्ष मध्यप्रदेश गौ-संवर्धन बोर्ड कार्य-परिषद अखिलेश्वरानंद गिरि ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को पत्र लिख कर जिले से बाहर भूसा निकासी पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। गिरि ने कहा कि कलेक्टर जिला गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के अध्यक्ष होते हैं, उन्हें अपने जिले को गौ-वंश और अन्य पशुओं के आहार का पर्याप्त भंडारण रखना चाहिए। वर्तमान में खलिहानों में पर्याप्त मात्रा में भूसा उपलब्ध है। गौ-संवर्धन बोर्ड द्वारा सभी पंजीकृत गौ-शालाओं को भूसा की खरीदी के लिए अनुदान राशि जारी कर दी गई है। जिन जिलों में पर्याप्त भंडारण नहीं हुआ है, अविलंब सुनिश्चित करें।

ईंधन के लिए भूसा बिक्री रोकें

अखिलेश्वरानंद ने कहा कि सूचना मिल रही है कि राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों के दलाल ईंधन के उपयोग के लिए फैक्ट्री मालिकों से बड़े दाम पर भूसा खरीद रहे हैं। भूसा की जिला बंदी कर पहले जिले की गौ-शालाओं में भूसे की सप्लाई करें। सुनिश्चित करें कि भूसा जिले से बाहर न जाने पाए।

खरीदें कंडे और गौ-काष्ठ

गिरि ने कहा कि जिलों की शासकीय और अशासकीय गौ-शालाओं में संरक्षित गौ-वंश के आहार (भूसा) की चिंता सर्वोपरि है। ईंधन के लिए उद्योग जगत गौ-शालाओं से कंडे और गौ-काष्ठ खरीदें। विशेषकर ईंट भट्ठों पर निगरानी रखी जाए। उन्होंने किसानों से भी अनुरोध किया कि भूसा विक्रय में गो-शालाओं को प्राथमिकता दें।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले-श्योपुर की धरती पर बरस रहा है विकास का रंग

केन्द्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में हुआ समारोह

श्योपुर के लिए वरदान सिद्ध होंगी सिंचाई की परियोजनाएं

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि श्योपुर बदल रहा है, यहां विकास की गंगा बह रही है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास और जन-कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं। सरकार, जन-प्रतिनिधि, प्रशासन और श्योपुरवासी मिल कर संकल्प लें कि प्रगति और विकास की इस दौड़ में पूरी प्रतिबद्धता के साथ हर संभव सहयोग करेंगे। साथ ही श्योपुर में शासकीय योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीब-कल्याण और विकास को समर्पित है। रंगपंचमी पर श्योपुर की धरती पर विकास का रंग बरस रहा है। श्योपुर जैसे पिछड़े जिलों की प्रगति के लिए राशि की कभी कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्योपुर में 768 करोड़ रुपए के मेडिकल कॉलेज भवन, मूंझरी वृहद सिंचाई परियोजना, प्रेमसर-रिनीखेड़ा मुढला मार्ग और सीएम राइज शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के शिलान्यास और 245 करोड़ 41 लाख के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने 167 करोड़ 58 लाख की लागत वाली चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण भी किया।

छह बांधों का निर्माण कराएंगे- मुख्यमंत्री ने कहा कि कूनो नदी पर 6 बांध का निर्माण कर 4 जिलों को सिंचित करने की व्यवस्था के लिए जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही चंबल सूक्ष्म सिंचाई योजना में सिंचाई सुविधा से छूटे गांवों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। चंबल सूक्ष्म सिंचाई योजना का लोकार्पण तथा मूंझरी बांध का निर्माण श्योपुर के लिए वरदान सिद्ध होगा।

अन्नदाताओं को सिंचाई की दो बड़ी सौगातें: सिंधिया

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश में जन-जन में विकास और विश्वास की अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि रंगपंचमी का दिन श्योपुर के लिए अविस्मरणीय है। आज जिले के विकास के लिए एक हजार करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन हुआ है। मुख्यमंत्री ने आज अन्नदाताओं को सिंचाई के क्षेत्र में दो बड़ी सौगातें दी हैं। एक का लोकार्पण तो दूसरे का भूमि-पूजन हुआ है, इससे क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। सिंधिया ने श्योपुर के विकास और अपने जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रीमंत माधो महाराज ने आवदा डेम के साथ ही 100 वर्ष पहले नैरोगेज ट्रेन की सुविधा श्योपुर को दी थी।

विदेशों में भी श्योपुर की पहचान: शर्मा

खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि वर्ष 2003 में श्योपुर जिले के हालात कैसे थे, उस स्थिति से हम सब अवगत है। श्योपुर की पहचान कूनों पालपुर, वीरपुर के जंगलों से होती थी। मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में अब श्योपुर, देश में ही नहीं, विदेश में भी पहचान बना रहा है। जिले में सिंचाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। मकूनों अभयारण्य में चीतों को बसाने की योजना ने देश-विदेश में श्योपुर को पहचान दिलाई है। यह परियोजना पर्यावरण संतुलन के क्षेत्र में भी उपयोगी है।

सिंचाई में आयी क्रांतिः सिलावट

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में क्रांति आयी है। राज्य सरकार कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज चंबल सूक्ष्म सिंचाई योजना के लोकार्पण और मूंझरी बांध के भूमि-पूजन से क्षेत्र के 86 गांव को लाभ मिलेगा। सिंचाई परियोजनाओं से 119 गांव में पानी की व्यवस्था होगी।

12 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी: तोमर

केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि श्योपुर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। श्योपुर दूरस्थ एवं पिछड़ा जिला है, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सडकें, विद्युतीकरण, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार हुआ है। श्योपुर जिला अब अग्रणी जिले के रूप में पहचाना जाने लगा है। केन्द्रीय मंत्री तोमर ने मूंझरी डेम के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस डेम को 2017 में ही स्वीकृति दे दी थी और इसका टेंडर भी हो गया था। 167 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत की चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से 12 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। कूनों नदी पर बनने वाले डेम की श्रृंखला में श्रीमंत माधवराव सिंधिया वृहद सिंचाई परियोजना पर भी कार्य किया जाएगा। इस परियोजना से श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना सहित अन्य जिले लाभान्वित होंगे।

पशुपालन मंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज का आभार माना

प्रदेश में पहली बार गौ-शालाओं को मिला 202 करोड़

भोपाल। जागत गांव हमार

पशुपालन मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं में गौ-वंश के पोषण के लिए वर्ष 2022-23 में अब तक की सर्वाधिक 202 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि प्रदाय की गई है। मंत्री ने गौशालाओं के लिए उपलब्ध कराई गई राशि के लिए मुख्यमंत्री और मध्यप्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। पटेल ने कहा है कि पिछले वर्षों की तुलना में यह राशि कई गुना अधिक है। इससे गो-शालाओं को काफी मदद मिली है और आत्म-निर्भरता में भी वृद्धि हुई है। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019-20 में 1583

गौशालाओं के एक लाख 69 हजार गौवंश के लिए 41 करोड़ 62 लाख, वर्ष 2020-21 में 1603 गौशालाओं के 2 लाख 43 हजार गौ-वंश के लिए 94 करोड़ 67 लाख, वर्ष 2021-22 में 1630 गौशालाओं के 2 लाख 76 हजार गो-वंश के लिए 77 करोड़ 89 लाख रुपए और इस वर्ष 1758 गौशालाओं के 2 लाख 78 हजार गो-वंश के लिए 202 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि प्रदाय की गई है। गौशालाओं में 20 रुपए प्रति गौ-वंश दिया जाता है, इसमें 15 रुपए चारा और 5 रुपए सुदाना के लिए शामिल है। प्रदेश में मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना और अशासकीय संस्थानों द्वारा 1758 गो-शालाएं संचालित कर निराश्रित गौ-वंशों का पालन-पोषण किया जा रहा है। गौशालाओं में गौ-काष्ठ, गोबर से गमले आदि बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है। गौशालाओं में जैविक खाद निर्माण, गौ-मूत्र औषधि, वर्मीपिट, गोबर गैस प्लांट आदि का निर्माण कर आय के स्रोत भी सृजित किए जाते हैं।

-पॉलिथिन खाने से शहर में घूम रहीं 70 फीसदी गायों की मौत

1400 गायों की मौत का महापाप

भोपाल। तस्वीर में नजर आ रहा पॉलिथीन का यह ढेर देखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसके पीछे की हकीकत रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दरअसल ये पॉलिथीन का ढेर एक गाय की मौत के बाद उसके पेट से निकला है। विदिशा रोड पर भदभदा के पास बड़े मैदान में ऐसे कई ढेर देखे जा सकते हैं। शहर की सड़कों पर घूमने वाली 10 हजार से ज्यादा गायों में से हर साल 2000 से ज्यादा की मौत हो जाती है। लेकिन, हैरानी यह है कि जितनी गायें मरती हैं उनमें से 70 फीसदी यानी करीब 1400 की मौत की वजह पॉलिथीन होती है। यह खुलासा पिछले दिनों जीवदया गौशाला में किए गए गायों के पोस्टमार्टम के दौरान हुआ। यहां 5 गायों का पोस्टमार्टम कराया गया था। यूं तो इन सभी गाय के पेट में पॉलिथीन मिली, लेकिन 4 गाय का रूमेन (आमाशय) पॉलिथीन से पूरी तरह भरा हुआ मिला। पशुप्रेमियों का कहना है कि पॉलिथीन में खाना रखकर अलग फेंकी गई पॉलिथीन भी भोजन की खुशबू के कारण गायें खा जाती हैं। इसलिए पॉलिथीन में खाना न रखें।

पॉलिथीन से भर जाता है आमाशय

नगर निगम के पशु चिकित्सक डॉ. एसके श्रीवास्तव ने बताया कि गाय जो भी खाती है, वह आमाशय में जाता है। खाने के साथ गई पॉलिथीन हजम नहीं होती और पेट में जमा होती रहती है। एक समय ऐसा आता है जब रूमेन पॉलिथीन से भर जाता है। गाय कुछ भी खाए पेट में जाने की जगह नहीं बचती। ऐसे में गैस बनती है। गाय कमजोर होने लगती है। पॉलिथीन और अन्य चीजों के कारण संक्रमण होता है और गाय की मौत हो जाती है।

- सड़कों पर घूम रही गायों के पेट में पॉलिथीन भरी हैं। पिछले दिनों हमने 5 गायों का पीएम कराया। हर गाय के पेट में पॉलिथीन मिली। एक गाय के पेट में 15 से 25 किलो तक पॉलिथीन मिलती है। 70 प्रतिशत गायों की मौत इसी वजह से हो रही है।

-डॉ. अजय रामटेके, उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)